आईडीबीआई सौदे को एलआईसी बोर्ड की हरी झंडी, होगी 51% हिस्सेदारी

नई दिल्ली16 जुलाई (ए)। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड ने आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी देते हुए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एस सी गर्ग ने कहा कि अब एलआईसी-आईडीबीआई बैंक डील के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। गर्ग ने कहा कि इस डील में अधिकांश स्टेक प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से खरीदी जाएगी।

इरडा से मिल चुकी है मंजूरी: उल्लेखनीय है कि एलआईसी को हिस्सेदारी खरीदने के लिए इरडा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस कदम से कर्ज के बोझ तले दबे सरकारी बैंक को 10,000-13,000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मिलेगा। सूत्रों ने कहा, एलआईसी- आईडीबीआई बैंक सौदे से बैंक के अल्पांश शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए खुली पेशकश लाई जाएगी।'

एलआईसी की इस वक्त आईडीबीआई बैंक में 10.82 फीसदी हिस्सेदारी है। इसे 51 फीसदी तक ले जाने के लिए उसे 40 फीसदी हिस्सेदारी और खरीदनी पड़ेगी। अभी तक के नियमों के अनुसार कोई भी बीमा कंपनी किसी भी कंपनी में 15 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। एलआईसी, आईडीबीआई बैंक के माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए ओपन ऑफर लाएगी। एलआईसी का उद्देश्य ओपन ऑफर के जरिए बैंक में 51 फीसदी इक्विटी खरीदना है। एलआईसी के पास फिलहाल आईडीबीआई बैंक की 11 फीसदी हिस्सेदारी है और बैंक के कुल लोन में टोटल स्ट्रेस्ड पोर्टफोलियो का हिस्सा 35.9 फीसदी है। मार्च तिमाही के अंत तक बैंक की ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स 55,588 करोड़ रुपए थीं।

बढ़ेगी गूगल की मुश्किलें, लग सकता है 20000 करोड़ का जुर्माना

Google

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूरोपियन यूनियन गूगल पर इस हफ्ते 20 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। आरोप है कि गूगल फोन बनाने वाली कंपनियों को अपना एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर तो फ्री में देती है, लेकिन इसके बदले वह गूगल वेब ब्राउजर और सर्च इंजन जैसे एप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करती है। यूरोपियन कंपनियों ने शिकायत की थी कि गूगल के दबाव में फोन निर्माता दूसरी कंपनियों के सर्च इंजन और ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करते हैं। गूगल ने कहा वह फोन निर्माताओं पर दबाव नहीं डालती है। यूरोपियन कमीशन को गूगल के सालाना टर्नओवर के 10 फीसदी तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। पिछले साल गूगल का टर्नओवर 110 अरब डॉलर था। यानी गूगल पर 11 अरब डॉलर (75,000 करोड़ रुपए) तक का जुर्माना लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतना जुर्माना शायद ही लगे। पर यह पिछले साल के 2.8 अरब डॉलर (19,000 करोड़ रुपए) से ज्यादा होगा। तब आरोप था कि सर्च के नतीजों में गूगल अपने विज्ञापनों को प्राथमिकता से दिखाती है।

नकली हो सकते हैं भारी छूट वाले आयातित सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद : उद्योग जगत

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग जगत का कहना है कि भारी छूट वाले उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण नकली उत्पादों में काफी तेजी आई है। उद्योग जगत का कहना है कि इनमें से कई उत्पाद आयात के टैग लगे भी होते हैं जो न केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि इससे स्वास्थ्य के प्रति गंभीर जोखिम भी है। लॉरियल इंडिया के प्रमुख (कानूनी मामले) एवं कंपनी सचिव पी.एल. शर्मा ने कहा, "नकली उत्पादों से ब्रांड की साख भी धूमिल हो रही है। ये उत्पाद आयात टैग तथा कीमतों के कारण उपभोक्ताओं को बिना संदेह आर्किषत करते हैं। भारी छूट के कारण कीमत नकली उत्पादों की खरीद में निर्णायक कारक बनकर उभरता है।" हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा, "यदि सरकार बौद्धिक संपदा उल्लंघन के इस तरह के मामलों को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए तो उद्योग जगत को काफी फायदा होगा।" ऑल इंडिया कॉस्मेटिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के निदेशक सतीश थिप्से ने दावा किया कि ज्यादातर नकली उत्पाद दिल्ली या मुंबई में मिलते हैं।

मोबाइल असोसिएशन ने जियो फोन के इंपोर्ट पर उठाए सवाल

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। रिलायंस जियो ने इस आरोप का खंडन किया है कि वह 4जी फीचरफोन जियोफोन को लाने के दूसरे ट्रेड रूट्स का सहारा लेकर इंपोर्ट ड्यूटी चुकाने से बचने की कोशिश कर रहा है। जियो ने कहा कि वह इन सभी हैंडसेट्स को भारत में ही बनाता है। जियो पर द मोबाइल असोसिएशन की अगुवाई में इंडियन मोबाइल हैंडसेट कंपनियों ने आरोप लगाया था कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जियोफोन को भारत में नहीं बना रही है। ऊरूकी मोबाइल अडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भूपेश रसीन ने ईटी से कहा, जियोफोन डिवाइसेज भारत में नहीं बनाए जाते हैं। हम समझते हैं कि जियोफोन डिवाइसेज चीन से आयात किए जा रहे हैं। टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (जियो) अब जीरो पर्सेंट कस्टम्स ड्यूटी की स्थिति का फायदा लेने के लिए इंडोनेशिया के जरिए बड़ी मात्रा में आयात करने की योजना बना रहा है। रसीन ने कहा कि पूरी तरह से असेंबल्ड डिवाइसेज को इंडोनेशिया के जरिए चीन से आयात करने से सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को नुकसान पहुंचेगा, जिसके मुताबिक लोकल कंपनियों ने बड़ी मात्रा में निवेश किया है। इंडोनेशिया दस देशों के असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान का सदस्य है। भारत ने आसियान के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। भारत चीन जैसे दूसरे बाजारों से पूरी तरह बनाए गए मोबाइल फोन के आयात पर 20 पर्सेंट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाता है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों पर जीएसटी लगाना गलत

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। एयरलाइन कंपनियों का वैश्विक संगठन आईएटीए ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया है और इस कराधान को गलत बताया है। संगठन का कहना है कि यह कई वैश्विक समझौतों के खिलाफ है जिसमें भारत भी पक्षकार है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 280 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों में एयर इंडिया, जेट एयरवेज तथा विस्तार शामिल हैं। आईएटीए के महानिदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलेक्जेंडर डी जुनिआक ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर जीएसटी लगाना गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विपरीत है जिसमें भारत भी पक्षकार है।" भारत में जीएसटी लागू किए जाने के बारे में उनकी राय पूछे जाने पर उन्होंने यह बात कही।

इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत पड़ोसी मुल्कों से पीछे

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। इंटरनेट स्पीड के मामले में फिलहाल हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। ब्रिटेन की इंटरनेट स्पीड टेस्टर कंपनी ओपनसिग्नल के मुताबिक भारत के पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार) की 4त्र डेटा स्पीड भारत के मुकाबले दोगुनी तेज है। ये देश विकसित बाजारों के मामले में भले ही पीछे हो लेकिन इंटरनेट स्पीड के मामले में ये दुनिया के अग्रणी देशों के करीब हैं। अगर दुनिया के अगर्णी देशों में इंटरनेट उपभोक्ताओं को मिल रही स्पीड की बात करें, तो अमेरिका, यूके और जापान में बेहतरीन स्पीड मुहैया हो रही है।

बफरिंग की समस्या भारत में आम : भारत में इंटरनेट यूजर्स के लिए बफरिंग की समस्या आज भी आम है। दुनिया के दूसरे देशों में इंटरनेट यूजर्स के लिए बफरिंग की समस्या न के बराबर ही है लेकिन हमारे देश में मोबाइल उपभोक्ता 4त्र नेटवर्क यूज करने के बावजूद अक्सर इंटरनेट में बफरिंग की समस्या से रू-ब-रू हो होते हैं। आज हमारे देश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां 4त्र से आगे बढ़कर अब 5जी की बात करने लगी हैं। घरेलू ब्रॉडबैंड के लिए फाइबर-बेस्ड पर आधारित कंपनियां भविष्य में 100Mbps स्पीड देने का दावा कर रही हैं। भारत में 4जी LTE (लॉन्ग टर्म ईवॉल्यूशन) की औसत स्पीड की बात करें, तो यह आज भी 6.1Mbps पर ही है, जबकि दुनिया के बाकी देश इंटरनेट स्पीड के मामले में हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। अपने देश में अगर हम इंटरनेट स्पीड की तुलना ग्लोबल स्पीड से करें, तो हम वैश्विक रूप से इस मामले में करीब एक तिहाई पीछे हैं। वैश्विक स्तर पर मोबाइल डेटा स्पीड का ग्लोबल एवरेज 17Mbps है।

इंटरनेट उपभोक्ताओं को मिल रही स्पीड: यूके की इंटरनेट स्पीड टेस्टर कंपनी ओपनसिग्नल के टेस्ट के आधार पर अगर हम भारत की 4त्र डेटा स्पीड की तुलना अपने पड़ोसी देशों से करें, तो श्रीलंका (13.95Mbps), पाकिस्तान (13.56Mbps) और मयांमार (15.56Mbps) के सामने हमारी स्पीड इनसे आधी भी नहीं है। ये देश विकसित बाजारों से कहीं पीछे माने जाते हैं लेकिन इंटरनेट स्पीड के मामले में ये दुनिया अग्रणी देशों के करीब हैं। अगर दुनिया अग्रणी देशों में इंटरनेट उपभोक्ताओं को मिल रही स्पीड की बात करें, तो अमेरिका में (16.31Mbps), यूके में (23.11Mbps), और जापान में (25.39Mbps) की स्पीड मुहैया हो रही है।

दुनिया के 124 देशों की रैंकिंग लिस्ट: अमेरिका की इंटरनेट स्पीड टेस्टर कंपनी ऊकला (Ookla) ने दुनिया के 124 देशों की रैंकिंग लिस्ट तैयार की है। इस सूची में भारत को 109वां स्थान मिला है। भारत करीब-करीब इस सूची के अंतिम पायदान के ही सबसे करीब दिखता है। ऊकला ने ये आंकड़े दुनिया भर में मौजूद 2त्र, 3त्र और 4त्र तकनीक पर टेस्ट कर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। भारत में इंटरनेट डाउनलोडिंग की औसतन स्पीड 9.12Mbps है, जो वैश्विक औसत (23.54Mbps) से कहीं ज्यादा नीचे है।

भारत में स्पीड कम होने की प्रमुख वजहः भारत में लगातार हर महीने कई लाख नए उपभोक्ता इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इससे इंटरनेट की स्पीड बनाए रखने का दबाव बढ़ता है। जानकारों के मुताबिक भारत में इंटरनेट स्पीड के धीमा होने का प्रमुख कारण स्मार्टफोन के क्षेत्र में आ रही यही महाक्रांति है। देश में इंटरनेट की धीमी स्पीड का एक अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि बड़े घनत्व में रहने वाली आबादी।

आईटी कंपनियों पर घटा विदेशी निवेशकों का भरोसा!

बेंगलुरु 16 जुलाई (ए)। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स इंडियन आईटी कंपनियों के शेयरों में अपना निवेश घटा रहे हैं। इंडियन आईटी होल्डिंग में उनकी कटौती की सबसे बड़ी चोट विप्रो और फिर इन्फोसिस को लगी है। दरअसल, आईटी मार्केट में डिजिटल टेक्नॉलजीज से मची हलचल के चलते इस सेक्टर में एडजस्टमेंट हो रहा है। इन्फोसिस के फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स ने कंपनी के शेयरों की बिकवाली जारी रखी जबकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेंपलटन इन्फ्रा कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे बड़े फॉरेन इनवेस्टर्स में शामिल हो गई। बेंगलुरु की इस कंपनी में फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स का एक्सपोजर 37 बेसिस प्वाइंट्स घटकर 34.82त्र रह गया है। टर्नअराउंड के दौर से गुजर रही कॉम्पिटिटर विप्रो के फॉरेन पोर्टफोलियो होल्डिंग में ज्यादा कमी आई। मार्च के अंत में कंपनी में फॉरेन इनवेस्टर्स की हिस्सेदारी 9.27 प्रतिशत से घटकर 8.72त्र रह गई। तेज ग्रोथ वाली बड़ी कॉम्पिटिटर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी फॉरेन होल्डिंग में कमी आई लेकिन उसकी मात्रा कम रही है।

डिस्काउंट पर कंट्रोल के लिए रिटेलर्स के कान पकड़ेगी ऐपल

कोलकाता 16 जुलाई (ए)। ऐपल ने भारत में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया है। इंडस्ट्री के चार सीनियर एग्जिक्यूटिव्स ने बताया कि इसके तहत कंपनी उन रिटेलर्स को ब्लैकलिस्ट करेगी, जो कीमतों में कटौती करने वाले होलसेलर्स से माल लेते हैं। साथ ही, कंपनी स्टोर्स के तेजी से एक्सपेंशन को रोकेगी और अमेरिका की तरह यहां भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर सेल को बढ़ावा देगी, जिससे रिटेलर्स तभी डिस्काउंट ऑफर करें जब ऐपल किसी कंज्यूमर प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत करे। अभी तक ऐपल के रिटेलर्स साल में किसी भी वक्त डिस्काउंट ऑफर करते रहते हैं।

एक एग्जिक्यूटिव ने बताया कि ऐपल ने यह कदम भारत की अपनी टीम से तीन सीनियर सेल्स एग्जिक्यूटिव्स के बाहर जाने के बाद उठाया है। साथ ही मिड-लेवल पर कंपनी के अभी और कुछ कर्मचारी कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब पूरी तरह से एक नई टीम सेल्स का मामला संभालेगी। कंपनी से इस्तीफा देने वाले तीन सीनियर एग्जिक्यूटिव्स में राहुल पुरी, जयंत गुप्ता और मनीष शर्मा शामिल हैं। पुरी कंपनी के नेशनल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेटर बिजनेस के हेड थे। वहीं गुप्ता आईफोन सेल्स, मॉडर्न ट्रेड और ऐपल प्रीमियम रिटेल स्टोर्स के हेड थे। शर्मा टेलीकॉम के लिए नेशनल सेल्स हेड थे। ऐपल ने इसके साथ ही अपने चीफ फाइनैंशल ऑफिसर गौरव दुग्गल की निगरानी में एक नई सेल्स ऑडिट टीम बनाई है। यह टीम मार्केट से किसी भी प्रॉडक्ट को चुनकर यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी की सेल्स प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन हो रहा है।

ऐपल के पूर्व इंडिया हेड संजय कौल ने सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट और सभी स्टोर्स में तेजी से विस्तार को बढ़ावा दिया था। हालांकि सिलिकॉन वैली स्थित ऐपल मुख्यालय को कौल का यह प्रयास पसंद नहीं आया था क्योंकि पिछले पांच सालों से ऐपल स्मार्टफोन का भारत में मार्केट शेयर 2 से 3 पर्सेंट पर ही स्थिर बना हुआ था। एक एग्जिक्यूटिव ने बताया, सफाई अभियान को इसी वजह से शुरू किया गया है। ऐपल को महसूस हुआ कि उसकी पिछली रणनीतियों की वजह से ब्रैंड के प्रीमियमनेस में कमी आई है और इसके चलते उसकी ऐवरेज सेलिंग प्राइस में गिरावट आई है। खासकर ऐसे समय में जब 30,000 रुपये से ज्यादा के स्मार्टफोन में सेगमेंट में सैमसंग, वनप्लस, गूगल और यहां तक कि शाओमी और ओप्पो जैसे नए ब्रैंड्स की वजह से कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है। ऐपल की इस नई रणनीति को कंपनी के नए इंडिया हेड माइकल कौलोंब की लीडरशिप में लागू किया जाएगा, जिन्होंने दिसंबर में संजय कौल की जगह ली थी।

थोक महंगाई दर जून में बढ़ी, 4.5 साल के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून में थोक महंगाई दर 4.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 5.77 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं मई में थोक महंगाई दर 4.43 फीसदी रही थी।

खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर भी बढ़ी है। महीने दर महीने आधार पर जून में खाद्य थोक महंगाई दर 1.12 फीसदी से बढ़कर 1.56 फीसदी रही है। वहीं महीने दर महीने आधार पर जून में मैन्युफैक्चरिंग थोक महंगाई दर 3.73 फीसदी से बढ़कर 4.17 फीसदी रही है। इसके अलावा महीने दर महीने आधार पर जून में फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 11.22 फीसदी से बढ़कर 16.18 फीसदी रही है। साथ ही महीने दर महीने आधार पर जून में प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई दर 3.16 फीसदी से बढ़कर 5.3 फीसदी रही है।

सब्जियों की महंगाई दर बढ़ी

महीने दर महीने आधार पर जून में सब्जियों की थोक महंगाई दर 2.51 फीसदी से बढ़कर 8.12 फीसदी रही है। हालांकि महीने दर महीने आधार पर जून में अंडे, मांस की थोक महंगाई दर 0.15 फीसदी से घटकर -0.27 फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर जून में दालों की थोक महंगाई दर -21.13 फीसदी से बढ़कर -20.23 फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर जून में आलू की थोक महंगाई दर 81.93 फीसदी से बढ़कर 99.02 फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर जून में प्याज की थोक महंगाई दर 13.20 फीसदी से बढ़कर 18.25 फीसदी रही है।

प्राइमरी मार्केट पर रिटेल निवेशकों की पैनी नजर

मुंबई 16 जुलाई (ए)। शेयर बाजार में रेकॉर्डतोड़ बढ़त जारी है और बाजार के सकारात्मक सेंटिमेंट्स इस समय प्राइमरी बाजार के लिए एकदम मुफीद हो चले हैं। यही वजह है कि लोढ़ा डिवेलपर्स और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड समेत कम से कम सात कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के अगले महीने तक पूंजी बाजार में दस्तक देने की उम्मीद है। इन आईपीओ से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटने की उम्मीद है। मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के अनुसार अगर बाजार में सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं तो जुलाई से सितंबर तक आईपीओ का सीजन होता है और उनका कहना है कि 30 सितंबर से पहले कई और आईपीओ बाजार में दस्तक देंगे। जानकारों का कहना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) की रुचि प्राइमरी बाजार में तेजी से बढ़ी है, उन्हें लग रहा है कि सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन काफी अधिक हो गया है। इसलिए वे इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाने के लिए प्राइमरी इश्यू यानी आईपीओ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। गौरतलब है कि एफपीआई ने इस साल अब तक प्राइमरी मार्केट में 17,612 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वहीं, इस दौरान उन्होंने 23,392 करोड़ रुपये बाजार से निकाले हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे में मर्चेंट बैंकर बड़े व पोटेंशल निवेशकों को रुझान को ध्यान में रखकर प्री इशू कंसलटेशन करते हैं और प्राइस बैंड डिस्कवरी में सहायक साबित होते हैं। इस समय डोमेस्टिक फंड भी काफी अच्छी पोजिशन में हैं और रिटेल निवेशक भी शेयर बाजार का स्वभाव समझते हुए बाजार में लंबे समय तक टिकने के मूड में आ रहे हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट के जानकार एस.पी. तुलस्यान का कहना है कि अब प्राइमरी मार्केट भी वैल्यूशन के मामले में सेकंडरी मार्केट के स्तर पर ही है।

10 करोड़ वर्कर्स को मिलेगी सोशल सिक्यॉरिटी!

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। सरकार 2019 में 10 करोड़ वर्कर्स के लिए अपने खर्च पर सामाजिक सुरक्षा योजना का ऐलान कर सकती है। 2012 में देश में 47.5 करोड़ लोग नौकरी कर रहे थे। इस आधार पर 22 फीसदी वर्कफोर्स के लिए अगले साल सोशल सिक्यॉरिटी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्यॉरिटी स्कीम पर काम कर रहा है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लाभार्थियों की संख्या तय करना पहला कदम है। एक अधिकारी ने बताया, 'इससे स्कीम के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, इसका पता चलेगा।' जेएनयू प्रफेसर संतोष मेहरोत्रा समिति ने यूनिवर्सल सोशल सिक्यॉरिटी स्कीम के संभावित लाभार्थियों की संख्या तय करने के लिए 2011-12 की तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को आधार बनाया है। पहले फेज में सभी वर्कर्स को स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी बेनेफिट दिए जाएंगे।

तेंदुलकर समिति की 2011-12 की गरीबी रेखा के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 13.7 फीसदी लोग इससे नीचे थे। वहीं, पूरे देश के लिए यह आंकड़ा 21.9 फीसदी था। मेहरोत्रा समिति अब स्कीम के लिए कितने फंड की जरूरत होगी, इस पर काम करेगी। लेबर मिनिस्ट्री ने देश के 50 करोड़ वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड-एज, डिसेबिलिटी, अन-एंप्लॉयमेंट और मैटरनिटी बेनेफिट्स सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रस्ताव रखा है। 50 करोड़ लाभार्थियों को चार हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले में वैसे गरीबों और वंचितों को रखा जाएगा, जो अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए खुद योगदान नहीं कर सकते। उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं, असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स इसके लिए कुछ योगदान दे सकते हैं, उन्हें सब्सिडाइज्ड स्कीम के तहत कवर किया जाएगा।